

पंजाब में हर खेत तक पहुंचाएंगे नहरी पानी: सीएम मान 7000 किलोमीटर और बिछाई जाएगी नई पाइपलाइन

चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर: मुख्यमंत्री

समर न्यूज़ | मोगा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा के भल्लूर में ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान ने कहा कि पंजाब के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए उनकी सरकार इस वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर और पाइपलाइनें बिछाएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें पहले ही बिछाई जा चुकी हैं, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वाटर रिचार्ज प्वाइंट भी बना रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा नकारी



गई पार्टियां मेरे खिलाफ इसलिए एकजुट हो गई हैं क्योंकि वे उनकी सरकार के कार्यों का मुकाबला नहीं कर सकतीं।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोग अपने शासनकाल के दौरान राज्य को लुटने वालों को कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आने

देंगे। लोक मिलनी के दौरान लोगों की भारी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में पाइपलाइनों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है ताकि सिंचाई संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें।

होशियारपुर में नहर में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत

-मेले में जा रहे युवक ने डूबते देखा, स्थानीय लोगों और पुलिस ने चलाया बचाव अभियान

समर न्यूज़ | होशियारपुर



पंजाब के होशियारपुर जिले में नहर में नहाने के दौरान 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किशोर अपने कुछ दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव में डूब गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पास में लगे मेले में जा रहे एक युवक ने किशोर को पानी में डूबते देखा और तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया और पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और

राहत टीम ने काफी तलाश के बाद किशोर को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि बरसात के मौसम में नहरों और तेज बहाव वाले जल स्रोतों में नहाने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है।

अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना, बीएसएफ और पंजाब पुलिस अलर्ट पर पंजाब में अर्धसैनिक बलों की नौ कंपनियां तैनात, बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

समर न्यूज़ | पठानकोट

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब पुलिस, भारतीय सेना, बीएसएफ और सिविल प्रशासन ने संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया है।

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जबकि पंजाब और पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालुओं की आवाजाही 1 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां उपलब्ध करवाई गई हैं, जिन्हें संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और कंपनियों की तैनाती की उम्मीद है।



स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पी.के. सिन्हा की अगुवाई में यात्रा की सुरक्षा तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय अंतर-राज्यीय बैठक भी की गई, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने, एजेंसियों के बीच तालमेल और श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा पर चर्चा हुई।

3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु पठानकोट रूट से गुजरेंगे। पठानकोट को मुख्य

ट्रांजिट जिला मानते हुए पंजाब पुलिस ने 5 सुरक्षा सेक्टरों में 65 किलोमीटर यात्रा रूट को कवर करने वाली बहु-स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है।

माधोपुर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी, नाके, रूट डोमिनेशन, सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गश्त की व्यवस्था की गई है। यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय

जालंधर में फर्जी रेलवे विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार एसी कोच में वीआईपी सुविधाएं लेने का आरोप टीटीई और रेलवे स्टाफ पर रौब झाड़कर करता था यात्रा, कार्यप्रणाली पर सवाल

पहचान पर संदेह होने के बाद आरपीएफ ने दबोचा

समर न्यूज़ | जालंधर

पंजाब के जालंधर में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खुद को रेलवे का विजिलेंस इंस्पेक्टर बताकर यात्राएं करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह लंबे समय से फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रेलवे अधिकारियों और टिकट चेकिंग स्टाफ पर धौंस जमाता था। इसी के सहारे वह एसी कोच में बिना वैध अधिकार के यात्रा करता और कई स्थानों पर वीआईपी सुविधाओं का लाभ भी उठाता था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आरोपी कई बार खुद को रेलवे विजिलेंस विभाग का अधिकारी बताकर ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल

उठाता था। वह कर्मचारियों से पूछताछ करता और निरीक्षण का दिखावा कर उन पर दबाव बनाता था। उसकी गतिविधियां काफी समय से संदेह के घेरे में थीं। हाल ही में जालंधर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान आरोपी को पहचान और दस्तावेजों की जांच की गई। पूछताछ में वह अपने पद और नियुक्ति से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की, जिसमें प्रारंभिक जांच में उसके फर्जी तरीके से पहचान का इस्तेमाल करने की बात सामने आई। जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी ने फर्जी पहचान के आधार पर कई बार एसी कोच में यात्रा की और रेलवे कर्मचारियों से विशेष व्यवहार भी हासिल किया। पुलिस

अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने कब से यह तरीका अपनाया, किन-किन ट्रेनों में यात्रा की और क्या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी इस धोखाधड़ी में शामिल था। **मामला दर्ज कर जांच शुरू:** आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों क भी ऐसे मामलों में सतर्क रहने और किसी भी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी अधिकारी बनकर दबाव बनाने की कोशिश करे तो इसकी तुरंत सूचना आरपीएफ या रेलवे प्रशासन को दें।

फाजिल्का में भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से गिराई गई 1 किलो 170 ग्राम हेरोइन बरामद

समर न्यूज़ | फाजिल्का

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे फाजिल्का जिले के जलालाबाद इलाके में सुरक्षाबलों ने एक बार फिर पाकिस्तानी तस्करों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सीमा क्षेत्र में ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर 1 किलो 170 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जानकारी के अनुसार, यह खेप ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई थी।

बरामद पैकेट पर रेडियम टेप लगा हुआ था, ताकि रात के अंधेरे में स्थानीय तस्कर इसे आसानी से ढूंढ सकें। जलालाबाद सदर थाना के SHO जुगराज सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी कानून-व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी

दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने सूचना दी कि गांव जोधा भैनी के खेतों के पास पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस और BSF के जवानों ने इलाके को सील कर दिया और खेतों में करीब ढाई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान खेत से एक लावारिस पैकेट बरामद हुआ।

जांच करने पर उसमें से 1 किलो 170 ग्राम हेरोइन मिली। एसएचओ जुगराज सिंह ने बताया कि हेरोइन की खेप को कब्जे में ले लिया गया है। अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सीमा पर बैठे पाकिस्तानी तस्करों के इशारे पर इस खेप को पंजाब या भारत में किस स्थानीय तस्कर ने रिसीव करना था।

समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस | समर एक्सप्रेस

पेट्रोल-डीजल की खरीद पर 200 लीटर की दैनिक सीमा समाप्त दिल्ली में नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से बड़ी राहत

कमर्शियल खरीदार फिर रिटेल पंपों से खरीद सकेंगे ईंधन

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर लागू अस्थायी प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता (कमर्शियल बायर्स) अब पहले की तरह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के रिटेल पेट्रोल पंपों से सीधे ईंधन खरीद सकेंगे। साथ ही, डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन प्रति वाहन की सीमा भी समाप्त कर दी गई है।

यह फैसला पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए अस्थायी नियमों की समीक्षा के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, जून में लागू गए प्रतिबंधों का उद्देश्य कालाबाजारी, जमाखोरी और ईंधन की अनुचित खपत को रोकना था। उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और खुदरा व थोक ईंधन कीमतों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। अब आपूर्ति सामान्य होने और बाजार में स्थिरता से लौटने के बाद इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से परिवहन कंपनियों, उद्योगों, निर्माण क्षेत्र और अन्य बड़े ईंधन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्हें अब अलग उपभोक्ता पंपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और देशभर के सामान्य पेट्रोल पंपों से भी ईंधन मिल सकेगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए पहले से लागू व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।

ईवी वाहन खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत 1 जुलाई से दिल्ली में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले मॉडलों पर लागू होगी।

सरकार का लक्ष्य राजधानी में प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। नई ईवी नीति में आगे चलकर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक



दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि कर छूट और अन्य प्रोत्साहनों से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। एक और जहां केंद्र सरकार के फैसले से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है, वहीं

दिल्ली की नई ईवी नीति स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों फैसले अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं—एक ईंधन आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए और दूसरा प्रदूषण कम कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए।

भाई ने कहा- परिवार ने नहीं किया नियुक्त; वकील ने मानहानि का लगाया आरोप

एजेंसी | पुणे

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। आरोपी सिया गोयल की ओर से पैरवी करने का दावा करने वाले अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल ने सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए, जिनसे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब साहिल गोयल ने मीडिया से कहा कि उनके परिवार ने अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव को सिया

की ओर से पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि परिवार की ओर से किसी अन्य वकील को नियुक्त किया गया है।

इसके बाद अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कानूनी नोटिस भेजते हुए इन बयानों को झूठा और मानहानिकारक बताया। नोटिस में श्रीवास्तव का कहना है कि सिया गोयल ने विधिवत वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है और यह दस्तावेज अदालत में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने साहिल से कथित आपत्तिजनक बयान वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में ऐसे आरोप नहीं लगाने की मांग की है। अस्थायी 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विभिन्न पहलुओं की जांच: उधर, साहिल गोयल अपने पहले के रुख पर कायम हैं। उनका कहना है कि परिवार ने श्रीवास्तव को अधिकृत नहीं किया और इस संबंध में अदालत के समक्ष भी अपना पक्ष रखा जाएगा। इस बीच, केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल यह विवाद केवल कानूनी प्रतिनिधित्व और कथित मानहानि तक सीमित है। 10 करोड़ रुपये के नोटिस में लगाए गए आरोपों पर अभी किसी अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया है। इस मामले में आगे की स्थिति न्यायालय की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही स्पष्ट होगी।

राजनीति नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने से बदला उच्च सदन का गणित

राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचा एनडीए गठबंधन

महिला आरक्षण लागू कराने की बड़ी संभावनाएं; संविधान संशोधन से जुड़े विधेयकों पर सरकार की रणनीति को मिल सकती है मजबूती

एजेंसी | नई दिल्ली

राज्यसभा में हाल ही में निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत हो गई है। नए सदस्यों के आने से गठबंधन उच्च सदन में दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के काफी करीब पहुंच गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कुछ निर्दलीय या अन्य दलों का समर्थन मिला, तो सरकार के लिए संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। एनडीए की बढ़ती



प्रावधानों में संशोधन का हो सकते हैं प्रयास गौरतलब है कि वर्तमान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को पारिसीमन (डिलिबिटेशन) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से जोड़ा गया था। सरकार ने 2026 में इन प्रावधानों में संशोधन का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा में अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए की मजबूत होती स्थिति ने राजनीतिक समीकरण जटिल बदले हैं, लेकिन महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं माना जा सकता। सरकार को संविधान संशोधन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव के लिए दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत जुटाने के साथ-साथ व्यापक राजनीतिक सहमति भी बनानी होगी। आने वाले संसदीय सत्रों में इस मुद्दे पर सरकार की रणनीति और विपक्ष के रुख पर सभी की नजर रहेगी।

ताकत के बीच एक बार फिर महिला आरक्षण को लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संविधान (131वां

संशोधन) विधेयक, 2026 लाकर 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को

33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रयास किया था। हालांकि, अप्रैल में यह विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका और पारित नहीं हो पाया था।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि सरकार भविष्य में इस विधेयक या इससे जुड़े संशोधित प्रस्ताव को दोबारा संसद में लाती है, तो राज्यसभा में बेहतर संख्या उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

हालांकि, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केवल राज्यसभा में ही नहीं, बल्कि लोकसभा में भी आवश्यक बहुमत हासिल करना अनिवार्य होगा। इसलिए केवल उच्च सदन में बड़ी ताकत से विधेयक अपने आप कानून नहीं बन जाएगा। दोनों सदनों में बहुमत जरूरी है।

सेना की वर्दी में बड़ा बदलाव, औपनिवेशिक दौर की कई परंपराओं को किया गया खत्म

आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 लागू, बंडी जैकेट को मिली जगह; ‘रॉयल’ शब्द हटेगा, कई औपचारिक नियम भी बदले

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय सेना ने अपनी वर्दी, औपचारिक पोशाक और समारोहों से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए औपनिवेशिक दौर की कई परंपराओं को समाप्त करने का फैसला किया है। सेना ने ‘आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026’ नाम से नया ड्रेस कोड जारी किया है, जो करीब आठ वर्ष बाद किया गया सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है। सेना का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य भारतीय पहचान, आधुनिक जरूरतों और व्यावहारिकता के अनुरूप ड्रेस नियमों को ढालना है, जबकि सैन्य अनुशासन और रेजिमेंटल परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा।

नई नियमावली के तहत औपनिवेशिक विरासत से जुड़े कई प्रतीकों और प्रथाओं को हटाया गया है। अब परेड के दौरान रिब्रूइंग ऑफिसर (मुख्य अतिथि) के लिए तलवार धारण करना अनिवार्य नहीं होगा। तलवार केवल परेड कमांडर और कुछ विशेष सैन्य समारोहों तक सीमित रहेगी। इसके



अलावा, लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे कुछ औपचारिक बेल्ट और अन्य सजावटी सैन्य उपकरण भी चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। सेना ने पुराने ब्रिटिश दौर के शब्द ‘रॉयल’ का उपयोग भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। नई ड्रेस पॉलिसी में भारतीय परंपरा को बढ़ावा देते हुए अधिकारियों के औपचारिक नागरिक परिधान में बंडी जैकेट को शामिल किया गया

है। साथ ही मौसम और परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया बैटल जैकेट भी लाया जा रहा है, जो वर्तमान सर्दियों की जर्सी की जगह लेगा। सेना का मानना है कि नई वर्दी भारतीय जलवायु के अधिक अनुकूल होने के साथ-साथ जवानों के लिए अधिक सुविधाजनक और कार्यक्षम होगी।

■ **विस्तृत दिशा-निर्देश जारी:** नई नियमावली में व्यक्तिगत साज-

सज्जा (ग्रूमिंग) से जुड़े मानकों को भी स्पष्ट किया गया है। पुरुष और महिला सैनिकों के लिए हेयरस्टाइल, टैटू, आभूषण और अन्य व्यक्तिगत पहनावे के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पूरी सेना में एकरूपता बनी रहे। महिला अधिकारियों को कुछ औपचारिक अवसरों पर सादे रंग की साड़ी या निर्धारित भारतीय परिधान पहनने की अनुमति भी दी गई है। सेना

अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव केवल वर्दी बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सैन्य परंपराओं को स्वतंत्र भारत की पहचान के अनुरूप विकसित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। हाल के वर्षों में सेना ने कई अन्य सुधार भी किए हैं, जिनमें स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग और सैन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है।

■ **सेना की पेशेवर छवि और मजबूत होगी:** रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नई ड्रेस पॉलिसी से भारतीय सेना की पेशेवर छवि और मजबूत होगी। उनके अनुसार, औपनिवेशिक दौर के प्रतीकों को हटाने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि सैन्य मूल्यां, अनुशासन और रेजिमेंटल गौरव में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नई वर्दी और नियम भारतीय सेना की बदलती पहचान को दर्शाते हैं।

किंग चार्ल्स के आधिकारिक विवरण से 500 साल पुरानी डिफेंडर ऑफ द फेथ उपाधि हटी

नई भाषा में ‘मल्टी-फेथ नेशन’ में सभी धर्मों के संरक्षण पर जोर, बदलाव पर बहस

एजेंसी। लंदन

ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक विवरण में बड़ा बदलाव किया गया है। ब्रिटिश शाही परिवार की वार्षिक सॉवरैन ग्रांट रिपोर्ट 2025-26 में सदियों पुरानी ‘डिफेंडर ऑफ द फेथ’ उपाधि का उल्लेख हटाकर नई शब्दावली अपनाई गई है।

अब आधिकारिक विवरण में कहा गया है कि सम्राट इंग्लैंड के चर्च के सुप्रीम गवर्नर हैं और ब्रिटेन जैसे बहुधार्मिक (मल्टी-फेथ) समाज में सभी आस्थाओं के लिए स्थान और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

‘डिफेंडर ऑफ द फेथ’ की उपाधि का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। वर्ष 1521 में पोप लियो दशम ने तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट हेनरी अष्टम को यह सम्मान प्रदान किया था। बाद में यह ब्रिटिश राजशाही की आधिकारिक परंपरा का हिस्सा बन गया और तब से हर सम्राट के औपचारिक परिचय में शामिल रहा। हालांकि, यह बदलाव संवैधानिक भूमिका में परिवर्तन नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, किंग चार्ल्स अब भी चर्च ऑफ इंग्लैंड के सुप्रीम गवर्नर हैं और उनकी



कानूनी तथा धार्मिक जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव केवल आधिकारिक विवरण की भाषा में किया गया है, जिससे आधुनिक और बहुधार्मिक ब्रिटेन की छवि को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके।

यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि किंग चार्ल्स ने 1994 में प्रिंस ऑफ वेल्स रहते हुए कहा था कि वह स्वयं को केवल एक धर्म का

नहीं, बल्कि सभी धर्मों का संरक्षक मानना पसंद करेंगे।

मौजूदा संशोधन को उसी सोच का विस्तार माना जा रहा है। हालांकि, इस बदलाव को लेकर ब्रिटेन में राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर बहस भी तेज हो गई है। कुछ लोगों ने इसे बदलते सामाजिक परिवेश के अनुरूप कदम बताया है, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक परंपरा से दूरी के रूप में देख रहे हैं।

अब यूजरनेम से होगी चैट, मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी कर सकेंगे बातचीत

■ प्राइवैसी बढ़ाने की तैयारी, नंबर की जगह मिलेगा यूनिक यूजरनेम; फीवर फिलहाल टैस्टिंग चरण में

एजेंसी। नई दिल्ली

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसके तहत उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर की बजाय यूनिक यूजरनेम के जरिए दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी नए व्यक्ति से चैट शुरू करने के लिए अपना फोन नंबर साझा करना अनिवार्य नहीं रहेगा। यह फीचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अधिक सुरक्षित रखना चाहते हैं।

यूजरनेम फीचर फिलहाल विकास (डेवलपमेंट) और टैस्टिंग चरण में है। कंपनी ने अभी इसे आम उपयोगकर्ताओं के लिए जारी नहीं किया है, लेकिन आईओएस और एंड्रॉयड के बीटा संस्करणों में इससे जुड़े संकेत मिले हैं। कंपनी की योजना है कि हर उपयोगकर्ता एक



यूनिक यूजरनेम चुन सके, जिसके जरिए दूसरे लोग उसे खोजकर संदेश भेज सकेंगे। यूजरनेम बनाने के लिए कुछ नियम भी तय किए जा रहे हैं। इसमें केवल अंग्रेजी के अक्षर, अंक और कुछ सीमित विशेष चिन्हों का उपयोग किया जा सकेगा। यूजरनेम किसी अन्य व्यक्ति से मेल नहीं खाएगा और पहले से मौजूद नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई यूजर अपना यूजरनेम बदलता है तो उसके संपर्कों को सिस्टम के माध्यम से इसकी सूचना भी मिल सकती है।

■ **प्राइवैसी नीति को और मजबूत करेगा:** विशेषज्ञों का मानना है कि यह फीचर व्हाट्सएप की प्राइवैसी नीति को और मजबूत करेगा। वर्तमान में किसी नए व्यक्ति से व्हाट्सएप पर बातचीत करने के लिए फोन नंबर साझा करना पड़ता है। यूजरनेम सुविधा लागू होने के बाद व्यवसाय, ऑनलाइन समुदाय, शैक्षणिक समूह और सोशल नेटवर्किंग के दौरान लोग अपना निजी नंबर सार्वजनिक किए बिना भी संपर्क कर सकेंगे। यह सुविधा टेलीग्राम, सिग्नल और डिस्कॉर्ड

जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध है और अब व्हाट्सएप भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल के महीनों में व्हाट्सएप ने कई नए फीचर पेश किए हैं, जिनमें बेहतर गोपनीयता नियंत्रण, चैट लॉक, एडवांस्ड चैट प्राइवैसी, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट और एआई आधारित सुविधाएं शामिल हैं। यूजरनेम फीचर को भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मैसेजिंग अनुभव मिल सके।

■ **सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जारी होगा:** हालांकि, व्हाट्सएप की ओर से इस फीचर की आधिकारिक लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की गई है। कंपनी का कहना है कि नए फीचर को चरणबद्ध तरीके से विकसित और परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षण सफल रहने पर आने वाले महीनों में इसे एंड्रॉयड, आईफोन और वेब संस्करण के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जा सकता है। फिलहाल उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।

नई गाइडलाइन जारी; मौजूदा 10वीं बैच को पूरी छूट, 9वीं के छात्रों को भी एक बार की राहत, स्कूल स्तर पर होगा तीसरी भाषा का मूल्यांकन

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत लागू की जा रही तीन-भाषा नीति (थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी) को लेकर बड़ा संशोधन किया है। बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पढ़ रहे मौजूदा कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर तीसरी भाषा का नया नियम लागू नहीं होगा। यानी इन छात्रों को पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी और उन्हें तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी।

सीबीएसई ने यह भी साफ किया है कि वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी एक बार के विशेष प्रावधान (वन-टाइम रिलेक्सेशन) का लाभ मिलेगा। ये छात्र जब 10वीं में पहुंचेंगे, तब भी उन्हें तीसरी भाषा की सीबीएसई

सीबीएसई का थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर यू-टर्न 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी



बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। हालांकि, कक्षा 9 से उन्हें तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य रहेंगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई छात्र पहले से अंग्रेजी और किसी विदेशी भाषा (जैसे फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश) का अध्ययन कर रहा है, तो उसे बीच सत्र में भाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को केवल एक भारतीय भाषा तीसरे विषय (आर3) के रूप में जोड़नी होगी।

इससे भाषा बदलने को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता काफी हद तक दूर हो गई है।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान कक्षा 9 बैच के लिए तीसरी भाषा (आर3) का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से होगा। जब यह बैच 2027-28 में कक्षा 10 में पहुंचेगा, तब भी आर3 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नई भाषा नीति को चरणबद्ध तरीके से

लागू करना और छात्रों पर अतिरिक्त परीक्षा का दबाव कम करना है।

■ **बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य:** बोर्ड ने दोहराया कि एनईपी-2020 के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है, लेकिन किसी भी छात्र को नई व्यवस्था के कारण नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसी कारण संक्रमण काल (ट्रांजिशन पीरियड) के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। स्कूलों को भी भाषा विकल्प, शिक्षकों की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीएसई के इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। पिछले कुछ सप्ताह से तीन-भाषा नीति को लेकर विभिन्न राज्यों, स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। नई गाइडलाइन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा 10वीं बैच और वर्तमान 7वीं से 9वीं तक के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी, जबकि भविष्य की कक्षाओं में नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

कैथोलिक आर्चडायसीज बाल यौन शोषण पीड़ितों को देगा 39.5 करोड़ डॉलर

एजेंसी। सैन फ्रांसिस्को

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के कैथोलिक आर्चडायसीज ने चर्च से जुड़े बाल यौन शोषण मामलों में ऐतिहासिक समझौता करते हुए करीब 530 पीड़ितों को 39.5 करोड़ डॉलर (395 मिलियन डॉलर) का मुआवजा देने पर सहमति जताई है। यह समझौता वर्षों से चल रहे मुकदमों के दिवालियापन (बैंकक्रप्सी) की कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आया है। अंतिम मंजूरी अमेरिकी दिवालियापन अदालत से मिलनी बाकी है।

आर्चबिशप साल्वातोरे कॉर्डिलियोन प्रत्येक पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से माफीनामा भी भेजेंगे। चर्च को बाल सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़े 14 प्रमुख सुधार लागू करने होंगे। इनमें यौन शोषण के विश्वसनीय आरोप झेल चुके पादरियों की सार्वजनिक सूची जारी करना, गोपनीयता समझौतों पर रोक लगाना व भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कड़े सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

पेज 3 एंकर स्टोरी

बालटाल से पवित्र गुफा तक बनेगा आधुनिक रोपवे, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को राहत

2029 तक अमरनाथ यात्रा में होगी केबल कार की सुविधा

■ पर्यावरणीय मानकों का भी रखा जाएगा ध्यान

एजेंसी। नई दिल्ली/श्रीनगर

बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को आने वाले वर्षों में बड़ी सुविधा मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने बालटाल से पवित्र (केबल कार) परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है।

योजना के अनुसार, परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2027 से शुरू किया जाएगा और इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पूरी होने के बाद अभी पैदल या टट्ट से 5 से 8 घंटे में तय होने वाला सफर महज 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

प्रस्तावित रोपवे बालटाल से अमरनाथ गुफा तक लगभग 11.6 किलोमीटर लंबा होगा। इसे केंद्र सरकार की ‘पर्वतमाला’ योजना के तहत विकसित किया जाएगा।



इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), तकनीकी सर्वेक्षण और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य कठिन पर्वतीय मार्ग पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित, तेज और हर मौसम में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में अधिकांश श्रद्धालु बालटाल मार्ग से लगभग 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल, घोड़े, पालकी या सीमित हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए पूरी करते हैं। खराब मौसम, ऊंचाई और कठिन रास्ते के कारण बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार श्रद्धालुओं को विशेष परेशानी का सामना करना

पड़ता है। रोपवे शुरू होने के बाद यात्रा न केवल आसान होगी, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता और राहत-बचाव कार्यों में भी तेजी आएगी।

सरकार का कहना है कि परियोजना के निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक संतुलन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। रोपवे के चालू होने से यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन में भी सुधार आने की उम्मीद है।

■ **कई रोपवे परियोजनाओं का हिस्सा:** यह परियोजना जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित कई रोपवे परियोजनाओं का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने अमरनाथ के अलावा शंकराचार्य मंदिर, धाजीवास ग्लेशियर, भद्रवाह, सनासर और दूधपथरी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए भी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

इनका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है। हालांकि, परियोजना को लेकर कुछ पर्यावरणविदों और स्थानीय संगठनों

ने हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी, कचरा प्रबंधन और यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता भी जताई है।

उनका कहना है कि निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वहीं, सरकार का दावा है कि सभी आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियां और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

■ **हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को लाभ:** विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्धारित समयसीमा के अनुसार काम पूरा होता है, तो 2029 से अमरनाथ यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

इससे हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलने के साथ जम्मू-कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

Good

DAY



समर न्यूज़ | लुधियाना

यह नई सुबह आपके जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सफलता का संदेश लेकर आए। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन खुशियों, शांति, तरक्की और शुभ पलों से भरा रहे। हर कदम पर सफलता आपके साथ रहे, यही शुभकामना है।

दमनप्रोत कौर
स्किन केयर कंसल्टेंट

हरियाणा में आज से मनरेगा की जगह लागू होगा वीबीजीआरएएम, 590 करोड़ मिलेंगे

दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बनी सहमति, आज जारी होगी अधिसूचना

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबीजीआरएएम) लागू किया जाएगा।

नई योजना के तहत हरियाणा को विभिन्न विकास कार्यों के संचालन के लिए 590 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सहमति बनी है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की



अध्यक्षता में 27 और 28 जून को नई दिल्ली में वीबीजीआरएएम को लागू करने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक और सम्मेलन

आयोजित किया गया था। इस बैठक में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी भाग लिया। डॉ. चौहान के अनुसार,

राज्य सरकार 1 जुलाई से योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप

योजना में आवश्यक संशोधन और प्रावधान शामिल करने की भी अनुमति दी है, ताकि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर में वीबीजीआरएएम के क्रिया-व्ययन के लिए 95 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। वहीं, हरियाणा सरकार भी अपने हिस्से के रूप में करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस नई योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए देशभर में नई व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

हरियाणा में चैनत जल आंदोलन पर सख्ती 30 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट बंद

भड़काऊ और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में कार्रवाई, शांति बनाए रखने की अपील

समर न्यूज़। चंडीगढ़/कैथल

हरियाणा के कैथल जिले के चैनत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय 30 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक या प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई है।

प्रशासन का कहना है कि इन अकाउंट्स के माध्यम से आंदोलन से जुड़ी भड़काऊ, भ्रामक और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही थी। प्रशासन के अनुसार, साइबर सेल और पुलिस लगातार सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। जिन अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं।

कई दौर की बातचीत

जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से कई दौर की बातचीत भी की है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रुप्त संदेशों को साझा करने से बचें। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली वार्ता पर सभी की नजर रहेगी।

अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अफवाह फैलाने या सामाजिक तनाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

इस बीच, आंदोलन से जुड़े पूर्व सरपंच को कई खाप पंचायतों का समर्थन मिल गया है। खाप प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की पानी

संबंधी मांगों को जायज बताते हुए प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की है।

साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा जाएगा और किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं किया जाएगा।

बहादुरगढ़-शकूर बस्ती रूट पर दौड़ी देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन

समर न्यूज़ | बहादुरगढ़

देश की पहली पर्यावरण अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का दिल्ली के शकूर बस्ती और बहादुरगढ़ के बीच सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन ने इस रूट पर अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इससे पहले इसी ट्रेन का जींद-सोनीपत रेलखंड पर परीक्षण किया जा चुका है, जहां इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलाया गया था।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन को विभिन्न रेलखंडों पर चरणबद्ध तरीके से चलाकर इसके प्रदर्शन और तकनीकी क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। ट्रायल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेन के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी खामी न रह जाए और इसे सुरक्षित व प्रभावी ढंग



से व्यावसायिक संचालन के लिए तैयार किया जा सके।

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन को दिल्ली ले जाया गया था। यह दोपहर करीब 2:25 बजे शकूर बस्ती से रवाना होकर बहादुरगढ़ पहुंची। इसके बाद शाम करीब चार बजे इसे वापस शकूर बस्ती भेजा गया। वहीं, अपने दूसरे ट्रायल रन के दौरान ट्रेन शाम करीब साढ़े सात बजे एक बार फिर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रायल के दौरान कुछ यात्री भी ट्रेन में सवार होकर

बहादुरगढ़ पहुंचे। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है और इसका व्यावसायिक संचालन शुरू करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन अधिकक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि बहादुरगढ़-शकूर बस्ती सेक्शन पर ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इस दौरान इसकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

गुरुग्राम में रील बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट एमजी रोड पर वायरल हुए वीडियो से मचा बवाल

समर न्यूज़ | गुरुग्राम

हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ युवाओं को खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों की ओर धकेलती नजर आ रही है।

शहर की सबसे व्यस्त और पॉश सड़कों में शामिल एमजी रोड पर एक युवक का चलती गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वायरल वीडियो में सहारा मॉल के सामने स्थित सर्विस लेन पर एक काले रंग की महिंद्रा बोलेरो तेज



रफ्तार में दौड़ती दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी के बोनट पर एक युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बैठा हुआ है, जबकि चालक लापरवाही और आक्रामक अंदाज में वाहन चला रहा है। घटना एमजी रोड की उस सर्विस लेन की बताई जा रही है, जहां पब, बार, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स होने के कारण दिन-रात भारी आवाजाही रहती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार वाहन को देखकर पैदल राहगीरों को पीछे हटकर खुद को सुरक्षित करना पड़ा,

जबकि अन्य वाहन चालकों ने संभावित दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्ताहांत के दौरान एमजी रोड पर तेज रफ्तार वाहनों, तेज संगीत और स्टंटबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा और शांति प्रभावित हो रही है।

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने गुरुग्राम पुलिस को टैग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, वाहन जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की मांग की है। पुलिस वाहन के पंजीकरण नंबर की पहचान कर रही है।

अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 वर्षीय मासूम, सेना ने संभाला मोर्चा



अंकुर कपूर | अंबाला
समर न्यूज़

हरियाणा के अंबाला के निकट स्थित धन्यौड़ा गांव में मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा सामने आया, जहां खेलते समय चार वर्षीय मासूम बच्चा 220 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया। घटना के बाद पूरे गांव



में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तत्काल बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चार वर्षीय निर्भय मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई के साथ खेतों में गया था। वह अपने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था, तभी अचानक

उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खुले पड़े गहरे बोरवेल में जा गिरा। घटना के समय परिजन पास ही मौजूद थे। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। उन्होंने तुरंत गांव के सरपंच को सूचना दी, जिसके बाद जिला प्रशासन और राहत-बचाव टीमों को मौके पर बुलाया गया। हादसे

की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और भारतीय सेना की मदद ली गई।

उपायुक्त स्वयं मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। बोरवेल के भीतर फंसे बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। वहीं, चिकित्सकों की

एक विशेष टीम एंबुलेंस सहित घटनास्थल पर तैनात है। बच्चे की स्थिति पर नजर रखने के लिए बोरवेल में कैमरा भी उतारा गया है।

सेना और प्रशासन की संयुक्त टीम युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही है और पूरे क्षेत्र की निगाहें मासूम के सुरक्षित बाहर निकलने पर टिकी हुई हैं।

एक इंजेक्शन ने छीन लिया ओलिंपिक का सपना चार बार के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान का करियर संकट में

समर न्यूज़ | रोहतक

राजस्थान के सीकर निवासी और चार बार के गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रीय स्तर के पहलवान विजय कुमार लांबा ने एक कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण अपना खेल करियर बर्बाद होने का आरोप लगाया है। विजय का कहना है कि ओलिंपिक में देश के लिए खेलने और पदक जीतने का उनका सपना एक गलत इंजेक्शन की वजह से टूटना नजर आ रहा है।

वर्तमान में रोहतक के गुरु मेहर सिंह अखाड़े में प्रशिक्षण ले रहे विजय कुमार लांबा ने बताया कि उन्हें हल्का बुखार होने पर शहर की देव कॉलोनी स्थित एक मेडिकल स्टोर से दवा लेने गए थे। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। इस दौरान गिरने से उनका



एक दांत टूट गया और कंधे में गंभीर चोट भी आई।

साथी खिलाड़ियों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती किया गया। विजय करीब चार दिनों तक कोमा में रहे। होश में आने के बाद उनकी स्मरण शक्ति पर गहरा असर पड़ा और वह अपने परिजनों तक को पहचानने में असमर्थ हो गए। इसके अलावा उन्हें लगातार दौरे पड़ने लगे, जिसके चलते उन्हें करीब 15 दिनों तक एक निजी

अस्पताल में उपचाराधीन रहना पड़ा। पीड़ित पहलवान का कहना है कि इस घटना ने न केवल उनके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनके खेल करियर और ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के सपने को भी गहरा आघात पहुंचाया है। होश में आने के बाद विजय कुमार लांबा ने रोहतक के पीजीआई थाना पुलिस में मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ बयान दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पंचकूला-मोरनी रोड पर दर्दनाक हादसा एक युवक की मौत

समर न्यूज़ | मोरनी

पंचकूला-मोरनी मार्ग पर गांव जल्लाह के समीप हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई और एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब तीनों युवक एक दो-दोहरा साइकिल पर सवार होकर मोरनी से बलदाना लौट रहे थे।

सूरज अपने भाई चंद्रपाल और मित्र अमन के साथ बाइक पर सवार था। गांव जल्लाह के पास पहुंचने पर अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते बाइक सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए तीनों घायलों को अपनी निजी गाड़ी से सेक्टर-6 नगरिक अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया।

अलर्ट शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पलवल में बारिश से पहले नगर परिषद अलर्ट

सुंदर कुंडू | पलवल
समर न्यूज़

मानसून के आगमन से पहले पलवल नगर परिषद ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरसात के दौरान लोगों को जलभराव और जल निकासी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर परिषद द्वारा शहर के प्रमुख नालों और नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, शहर के कुछ इलाकों में अभी भी नालों में गंदगी और कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं।

नगर परिषद की ओर से बरसाती सीजन से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई कार्य लगातार कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रमुख नालों और नालियों की व्यापक स्तर पर सफाई की जा रही है, ताकि बारिश



के दौरान पानी की निकासी सुचारु रूप से होती रहे और जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। नगर परिषद के चेयरमैन डॉ. यशपाल ने बताया कि सफाई अभियान को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में

मानसून से पूर्व शहर के सभी प्रमुख नालों और नालियों की सफाई कराई जा रही है, जबकि दूसरे चरण में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद दोबारा सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद

ने बरसाती मौसम को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जलभराव संभावित क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान की गई है और वहां अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा, जल निकासी के लिए पंप सेट भी तैयार रखे गए हैं।

करनाल में बड़ा एक्शन: पांच बदमाश हथियारों के साथ किए गिरफ्तार

समर न्यूज़ | करनाल

पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गिरोह से जुड़े पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 अवैध पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हरियाणा और पंजाब में दो बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, जिसे पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया।

सीआईए-1 के प्रभारी सदीप कुमार ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 29 जून को पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश भारी मात्रा में हथियारों के साथ कुटेल बाइपास क्षेत्र में आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई की और पांच आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

बहन से विवाद: साले ने जीजा पर की फायरिंग, बाथरूम में छिप बचाई जान

समर न्यूज़ | हांसी

शहर के आर्य नगर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया, जब एक युवक ने अपनी बहन के साथ हुए विवाद से नाराज होकर कथित तौर पर अपने जीजा पर गोली चला दी। घटना में पीड़ित बाल-बाल बच गया और उसने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके से गोली का खोल बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आर्य नगर निवासी गुरदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार दिन में उसका अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद उसकी पत्नी का भाई कमलदीप चेची, जो हिसार का निवासी है, घर पहुंचा और अपनी बहन को अपने साथ ले गया।

आरोप है कि इसके बाद देर रात करीब एक बजे कमलदीप दोबारा गुरदीप के घर पहुंचा और

गेट फांदकर अंदर घुस गया। घर में प्रवेश करते ही उसने गुरदीप पर फायरिंग कर दी। अचानक हुए हमले से घबराकर गुरदीप बाथरूम में जाकर छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई। आरोपी द्वारा चलाई गई गोली बाथरूम के दरवाजे में जा लगी। घटना के बाद गुरदीप ने तुरंत डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी सुखजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की।

शहर थाना के जांच अधिकारी एसआई रामपाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से रात करीब एक बजे सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। उन्होंने बताया कि पीड़ित सुरक्षित है और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हिमाचल के जहालमा नाले में अचानक बाढ़, 150 पर्यटक और स्थानीय लोग सुरक्षित निकाले गए

लाहौल-स्पीति में अस्थायी पुल बनाकर चला रेस्क्यू अभियान; 2-3 जुलाई को भारी बारिश और अगले छह दिन आंधी-तूफान का अलर्ट

समर न्यूज़ | शिमला

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में स्थित जहालमा नाले में सोमवार देर रात अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 150 पर्यटक और स्थानीय लोग कुछ समय के लिए फंस गए।

सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और अन्य बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। राहत दलों ने अस्थायी पुल तैयार कर सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। किसी के हाताहत होने की सूचना नहीं है।

प्रशासन के अनुसार, भारी बारिश और ऊपरी इलाकों से आए तेज पानी के कारण जहालमा नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे सड़क संपर्क प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहन तथा यात्री फंस गए।

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर भाजपा का कांग्रेस सरकार पर हमला

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज़

हमीरपुर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह बन्याल ने प्रदेश सरकार पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बिना सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी किए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है।

उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और कई आवश्यक सुविधाएं तथा व्यवस्थाएं अधूरी हैं। विक्रम सिंह बन्याल ने कहा कि हाल ही में हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। विभिन्न कमियों को चिन्हित किया गया और संबंधित अधिकारियों को उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए।

सुंदनगर के जयदेवी में देवदार का अवैध कटान तस्करी के आरोप में 3 तस्कर गिरफ्तार, दो भागे

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज़

सुकेत वन मंडल के अंतर्गत जय देवी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध देवदार कटान और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रात्रि गश्त के दौरान की गई इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में देवदार की अवैध लकड़ी, एक पिकअप गाडी से बरामद की है।

मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि वन विभाग भी अलग से कानूनी कार्रवाई करेगा। रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि डिप्टी रेंजर रामलाल के नेतृत्व में जय देवी वन परिक्षेत्र की टीम च्योरा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान टीम ने सदिग्ध गतिविधि देख एक पिकअप वाहन को रोककर उसकी



बचाव दल ने स्थिति का आकलन करने के बाद अस्थायी पुल बनाकर चरणबद्ध तरीके से लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद मार्ग को यातायात के लिए बहाल करने का काम शुरू किया गया। इस

बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है।

विभाग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं

और बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से 2 और 3 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने और मौसम

संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है।

■ **अचानक बाढ़ का खतरा:** लाहौल-स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सभी संबंधित जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों की निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी तैनात की जाएंगी।

विमल नेगी प्रकरण: पत्नी ने राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग

संज़ू | शिमला
समर न्यूज़

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के दिवंगत चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले में उनकी पत्नी किरण नेगी ने राज्यपाल से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। सोमवार को हिमाचल जनजातीय लोक अधिकार महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ राजभवन पहुंचीं किरण नेगी ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

किरण नेगी ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दौरान दो अधिकारियों हरिकेश मीणा और देसराज के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े तथ्य सामने आने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि इन तथ्यों के बावजूद अब तक संबंधित

आपदा का बीत गया एक साल सराज के हाल अब भी बेहाल

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर उठाए सवाल



■ **कहा- सराज में अब भी सबकुछ अस्थायी तौर पर ही बहाल**
■ **सीएम को आपदा प्रभावितों की चिंता नहीं, वो सिर्फ मस्ती में सरकार चलाने में व्यस्त**

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज़

पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सराज में आपदा का एक साल बीतने के बाद भी हाल-बेहाल हैं। सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है।

गत वर्ष 30 जून को ही सराज में भूषण आपदा आई थी जिसमें 33 लोगों की जानें चली गई थी और सैंकड़ों लोग घर से बेघर हो गए थे। अकेले स्त्राज क्षेत्र में ही एक हजार करोड़ से अधिक के नुकसान का आंकलन किया गया था। जयराम



ठाकुर ने कहा कि आज भी सराज के लोग अस्थायी सुविधाओं के साथ जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को अस्थायी तौर पर ही बहाल किया गया है।

जरा सी बारिश होने पर सारी अस्थायी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां तक की सरकार 2023 की आपदा के जख्मों को भी नहीं भर पाई है। 150 करोड़ की पानी की योजना अभी तक बंद पड़ी है जिससे तीन दर्जन पंचायतों के लोगों को परेशानी

झेलनी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कई बार सराज के हालातों का मुद्दा सदन के अंदर, बाहर, सीएम और डिप्टी सीएम के समक्ष उठाया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली।

उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम को इस वकत सराज का दौरा करके हालातों का जायजा लेने को कहा, ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम को जनता की कोई परवाह नहीं है वह सिर्फ मस्ती में सरकार चलाने में ही व्यस्त हैं।

धर्मशाला नगर निगम के तीन पार्षदों पर सरकारी भूमि अतिक्रमण की पुष्टि

राहुल | धर्मशाला
समर न्यूज़

नगर निगम धर्मशाला के तीन निर्वाचित पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। प्रशासन का कहना है कि मामले में नगर निगम अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन को तीन पार्षदों और उनके परिजनों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों के आधार पर एसडीएम धर्मशाला के माध्यम से विस्तृत जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में



सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। उपायुक्त ने कहा कि जांच में अतिक्रमण पाए जाने के बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

साथ ही नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। अब सरकार संबंधित नियमों के अनुसार उचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया

कि शिकायत चुनाव के बाद प्राप्त हुई थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होती। यदि किसी भी समय शिकायत मिलती है और जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं, तो प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करता है। उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में भी सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रारंभिक जांच के दौरान शिमला पुलिस की ओर से कुछ अहम सबूतों को प्रभावित करने या मिटाने की कोशिश की गई। किरण नेगी ने मांग की कि इस पहलू की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। किरण नेगी ने

बताया कि उनका परिवार जल्द ही हरिकेश मीणा और देसराज के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक अलग शिकायत सीबीआई को सौंपेगा। उनका कहना है कि एजेंसी उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने राज्यपाल से पूरे मामले की निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

गौरतलब है कि एचपीपीसीएल के तत्कालीन चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च 2025 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। करीब आठ दिन बाद 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील से बरामद हुआ। इस घटना के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉर्पोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा,

निदेशक देसराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। परिवार की शिकायत के आधार पर 19 मार्च 2025 को न्यू शिमला पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। उसी दिन राज्य सरकार ने तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा और निदेशक देसराज को उनके पदों से हटा दिया।

हालांकि, पुलिस जांच से असंतुष्ट परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 23 मई 2025 को जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में लेकर विभिन्न पहलुओं की पड़ताल शुरू की। परिवार का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है और वे निष्पक्ष जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आने की उम्मीद कर रहे हैं।

नरघोटा हादसा: प्रशासन ने शुरू की जांच, परिवार को मिलेगा मुआवजा

राहुल चावला | धर्मशाला
समर न्यूज़

धर्मशाला के पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरघोटा में हुए सड़क हादसे में 30 वर्षीय अक्षय कोड़ा की मौत के मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। मृतक युवक के परिजनों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जिला प्रशासन ने मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है।

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हादसा चालक की लापरवाही, वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ। साथ ही सड़क

की बनावट, सुरक्षा व्यवस्था और डिजाइन का भी बारीकी से परीक्षण किया जाएगा ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके। डीसी ने कहा कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा आपदा राहत नियमावली के तहत मिलने वाला पूरा मुआवजा भी नियमानुसार शीघ्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ परिवार के साथ खड़ा है।

सड़क सुरक्षा को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अदि जांच में सड़क की डिजाइन या अन्य तकनीकी खामियां सामने आती हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

मनीषा मित्तल हत्याकांड में भाई हिमांक ही निकला मास्टरमाइंड, कारोबारी समेत काबू

पुलिस का दावा- संपत्ति और कारोबारी विवाद में रची गई हत्या की साजिश

समर न्यूज़ | शिमला

बहुचर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने मामले के कथित मास्टरमाइंड हिमांक मित्तल और उसके कारोबारी साझेदार गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर मनीषा मित्तल की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले दो कथित शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक

जांच में पारिवारिक संपत्ति और कारोबारी विवाद को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। आरोप है कि हिमांक ने अपने साझेदार गोविंद के साथ मिलकर सुगुरी देकर वारदात को अंजाम दिलाया।

पुलिस के मुताबिक, पहले गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारीयां मिलीं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कोल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हिमांक और गोविंद की भूमिका सामने आई।

दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि साजिश के अन्य पहलुओं की जांच की जा सके। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं

कि हत्या की योजना कब बनाई गई, इसके लिए कितनी रकम तय हुई और क्या इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी वित्तीय और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद अदालत में पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया जा सकता है।

वहीं, आरोपियों का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा।

डॉ. राजीव बिंदल ने विकास और लोकतंत्र के मुद्दों पर कांग्रेस घेरा

संज़ू | शिमला
समर न्यूज़

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संगठनात्मक जिला महामू के प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और विकास कार्यों को लेकर गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और उड़क सरकार को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।

डॉ. बिंदल ने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद भी कई स्थानों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और

डिप्टी मेयर के चुनाव लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा जनदेश का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे अभी भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एचपीएमसी के माध्यम से बागवानों के भुगतान लंबित हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान युवाओं और महिलाओं से कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित स्तर पर पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारी, परिवहन कर्मचारियों के मुद्दे और महिलाओं के लिए घोषित आर्थिक सहायता जैसे विषयों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

पूजा-अर्चना

आईआईटी मंडी के नए शोध ने वैज्ञानिकों को सोचने पर किया मजबूर

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के वैज्ञानिकों ने पौधों पर किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन के जरिये चेतना और बेहोशी (एनेस्थीसिया) के प्रभाव को समझने की दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि जब पौधों को बेहोशी की दवा दी गई तो उनकी कोशिकाओं ने बेहद व्यवस्थित और एक समान प्रतिक्रिया दिखाई। खास बात यह रही कि यह प्रतिक्रिया उन पौधों में भी देखने को मिली जिनमें न तो मस्तिष्क होता है और न ही तंत्रिका तंत्र। यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं एडवांस्ड



बायोलॉजी और केमिकल एंड बायोमेडिकल इमेजिंग में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से यह समझने में मदद मिल सकती है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित प्रक्रिया है या फिर जीवित कोशिकाओं में भी किसी स्तर पर इसकी उपस्थिति संभव है।

■ **टमाटर और बैंगन के पौधों पर किया गया विस्तृत अध्ययन:** शोध के लिए वैज्ञानिकों ने टमाटर और बैंगन के पौधों की जड़ों की जीवित कोशिकाओं का चयन किया। आधुनिक माइक्रोस्कोपी तकनीक की सहायता से कोशिकाओं के

भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का वास्तविक समय में अवलोकन किया गया। इस दौरान यह समझने का प्रयास किया गया कि बेहोशी की दवा पौधों की कोशिकाओं के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस शोध का नेतृत्व आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा, प्रोफेसर चयान कांति नंदी तथा उनकी शोध टीम ने किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधों की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन उम्मीद से कहीं अधिक व्यवस्थित और समन्वित हुए गए।

■ **जड़ों के अग्रभाग को बनाया अध्ययन का केंद्र:** वैज्ञानिकों ने पौधों की जड़ों के सबसे आगे वाले हिस्से का चयन इसलिए किया क्योंकि यही भाग मिट्टी में मौजूद पानी, पोषक तत्वों और अन्य

पर्यावरणीय संकेतों को सबसे पहले महसूस करता है। यही क्षेत्र पौधे की वृद्धि और संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह हिस्सा पौधे के लिए सूचना प्रसंस्करण केंद्र की तरह कार्य करता है। इसी कारण उन्होंने इस क्षेत्र की कोशिकाओं में होने वाले बदलावों का गहन अध्ययन किया।

■ **कोशिकाओं में दिखा क्रमबद्ध परिवर्तन:** दवा का प्रभाव पड़ते ही कोशिका के विभिन्न अंग एक निश्चित क्रम में अपनी गतिविधियां कम करने लगे। सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन से जुड़े हिस्से प्रभावित हुए। इसके बाद अन्य कोशिकीय संरचनाएं क्रमशः निष्क्रिय होती चली गईं और अंत में कोशिका का केंद्र (न्यूक्लियस) प्रभावित हुआ।

नयना देवी व जुजुआला कॉलेजों में संकाय बहाली पर जताया आभार

समर न्यूज़ | शिमला

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम लाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने जिला बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नयना देवी जी में वाणिज्य संकाय और राजकीय महाविद्यालय जुजुआला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों को बहाल करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

राम लाल ठाकुर ने कहा कि इन संकायों की बहाली से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही इन विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके घर-द्वार के निकट



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वर्तमान सरकार के व्यावहारिक एवं दूरदर्शी प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रदान करने में देश में 21वें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य की रैंकिंग 21वें स्थान पर फिसल गई थी।

न्यायिक जांच होना बाकी है।
 :यासीन मलिक पिलहाल ए
 अन्य आतंकवाद वित्तपोषण (टे
 फंडिंग) मामले में आजीव
 कारावास की सजा काट रहे हैं।
 इस नए मामले में अभी अदालत
 ने आरोप तय नहीं किए हैं और
 आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों
 की न्यायिक जांच होना बाकी है।
 इसलिए इन आरोपों पर अंतिम
 फैसला अदालत की सुनवाई के ब
 ही होगा।

वार्ड-81 में सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट पर फोकस, रोजाना लोगों की समस्याएं सुनकर होती है दिन की शुरुआत: मंजू गुप्ता



लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

सेंट्रल हलके के वार्ड नंबर-81 की भाजपा पार्षद मंजू गुप्ता ने कहा कि वार्ड के विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। करीब 11 हजार मतदाताओं और पांच मोहल्लों वाले इस वार्ड में उन्हें पिछले नगर निगम चुनाव में 1723 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि वार्ड के विकास कार्यों में उनके पति इंदर अग्रवाल हमेशा उनके साथ मिलकर काम करते हैं।

मंजू गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2012 में इंदर अग्रवाल वार्ड के पार्षद चुने गए थे, जबकि वर्ष 2018 से उन्हें जनता की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास और सहयोग के दम पर विकास कार्य लगातार जारी हैं। इंदर अग्रवाल ने कहा कि उनका परिवार शुरू से ही लोगों के सुख-दुख में शामिल

जनता का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत विकास कार्यों में नहीं आने देंगे रुकावट



रहा है। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करवाना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी दिन की शुरुआत ही लोगों के बीच जाकर या उनसे संपर्क कर उनकी समस्याएं जानने से होती है। रोजाना अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहकर वे लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछते हैं और संबंधित विभागों के माध्यम

से उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि लोगों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ा रहना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि वार्ड में सड़कों और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई विकास कार्य कराए गए हैं। हरचरण नगर, शिवजी नगर, कश्मीर नगर और रणजीत सिंह पार्क की नई सड़कों

के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक निगम की ओर से टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। इंदर अग्रवाल ने कहा कि सीवरेज और पानी की पाइपलाइन की नियमित मरम्मत करवाई जाती है। वार्ड में सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें लगावाई गई हैं और जरूरत वाले स्थानों पर सुपर सक्शन मशीनों की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि जलभराव

की समस्या का समय रहते समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि वार्ड कार्यालय में स्टाफ तैनात है, जो क्षेत्र के लोगों के सरकारी योजनाओं से जुड़े ऑनलाइन फॉर्म और अन्य आवश्यक दस्तावेज निःशुल्क भरने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

पंजाब मंडी बोर्ड फील्ड इम्प्लाइज यूनियन की नई टीम सर्वसम्मति से गठित कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन को सौंपा मांगपत्र

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

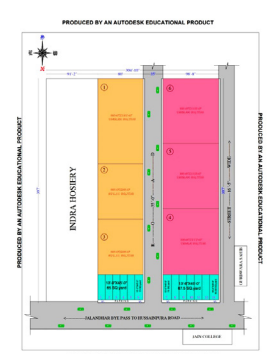
पंजाब मंडी बोर्ड फील्ड इम्प्लाइज यूनियन की जिला इकाई की बैठक मंगलवार को गिल मंडी (पानी वाली टैंकी) में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर यूनियन नेताओं ने पंजाब मंडी बोर्ड प्रबंधन से कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई। बैठक में यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरमीत सिंह (कोट ईंसे खां, मोगा), सरपरस्त खुशवंत सिंह बाजवा (लुधियाना) और सहायक जनरल सचिव सुविंदर सिंह भट्टी (फरीदकोट) विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में प्रबंधन को कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से शिंगारा सिंह को जिला चेयरमैन, दिलप्रीत सिंह को जिला प्रधान, प्रिंस कुमार बॉबी को वरिष्ठ प्रधान, जगतार सिंह को उपाध्यक्ष, गुरिंदर सिंह को महासचिव, गुरदीप सिंह को कोषाध्यक्ष, दिनेश भगत को प्रेस सचिव, लखबीर सिंह को



प्रचार सचिव, परमजीत सिंह को सलाहकार तथा सरजीत सिंह और बिंदर सिंह को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। बैठक में यूनियन ने मांग की कि विंग साइड, डीएमयू कार्यालयों, मार्केट कमेटियों, सिविल विंग, जन स्वास्थ्य विंग और बिजली विंग में कार्यरत कच्चे कर्मियों को नियमित किया जाए। सभी कर्मचारियों को ईएसआई एवं ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा सरकार द्वारा घोषित 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि तुरंत जारी की जाए। इसके अलावा वर्ष 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, वर्ष 2011 से रिवर्ट किए गए 24 इलेक्ट्रिशियनों को बहाल करने, सुपरवाइजर श्रेणी के रिक्त पदों पर हेल्थरों को पदोन्नत करने, कर्मचारियों का लंबित 18 प्रतिशत को महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने

तथा मंडियों में ठेकेदारों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की भी मांग की गई। यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यदि समय रहते इनका समाधान नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को मजबूर होगी। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब मंडी बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा। बैठक में संजीत भगत, दया राम, अर्जुन कुमार, रणजीत सिंह (लुधियाना), भूपिंदर सिंह, सुशील कुमार, जगतार सिंह, हरदीप सिंह, कमलजीत सिंह, राम सजीवन, गुरिंदर सिंह, बिंदर सिंह, चरणजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

अवैध कॉलोनियों का 'काला कारोबार'! सपनों पर डाका...



राहुल शर्मा | लुधियाना
समर न्यूज़

शहर के मल्होत्रा पैलेस से सटे हुसैनपुरा और लाधिया क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल चलने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी कॉलोनाइजर्स ने खेती योग्य भूमि पर बिना आवश्यक मंजूरीयों के प्लॉट काटकर बेच दिए, जिससे सैकड़ों परिवारों की जीवनभर की कमाई दांव पर लग गई। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं, जबकि अवैध प्लॉटिंग का कारोबार लगातार चलता रहा।

पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने किराये के मकानों से छुटकारा पाने और अपना घर बनाने के उद्देश्य से किस्तों पर प्लॉट खरीदे थे। बाद में जब बैंक से मकान निर्माण के लिए ऋण लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कॉलोनियों वैध नहीं हैं। इसके चलते बैंक ने ऋण देने से इन्कार कर दिया। लोगों का कहना है कि यदि पहले ही सही जानकारी मिल जाती तो वे अपनी गाड़ी कमाई इस तरह दांव पर नहीं लगाते।

सूत्रों का दावा है कि संबंधित विभाग ने कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कर और सीमित स्तर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई का दिखावा किया, लेकिन इसके बाद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद हैं।
■ रजिस्ट्रियों पर उठे सवाल... सूत्रों के अनुसार, यदि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां हुई हैं तो यह जांच का विषय है कि किन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें मंजूरी मिली। कुछ लोगों ने फर्जी एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रियां होने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बरसाने के लिए 16 जुलाई को होंगे रथ पर सवार, शहर में उत्साह



लक्की भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज़

इस्कोन एवं भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव कमेटी की ओर से आगामी 16 जुलाई, वीरवार को श्री दुर्गा माता मंदिर, जगयाओं पुल से शाम 4 बजे 30वीं विशाल, भव्य एवं ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा बड़े श्रद्धाभाव एवं उत्साह के साथ निकाली जाएगी।



रथयात्रा को लेकर शहरभर में भक्तों के बीच विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। उपरोक्त शब्दों का प्रकटावा कमेटी के चेयरमैन राजेश बांडा ने किया। रथयात्रा को सफल बनाने के लिए कमेटी के सदस्य एवं जगन्नाथ सेवक दिन-रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। रथयात्रा महोत्सव कमेटी द्वारा महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज के गणमान्य व्यक्तियों, धार्मिक संस्थाओं,



सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं को रथयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। राजेश बांडा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन देने व अपनी कृपा बरसाने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। ऐसे दिव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनना हर श्रद्धालु के लिए गौरव की बात है। कमेटी के महासचिव संजीव सूद बांका ने बताया कि भगवान



जगन्नाथ जी के रथ को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। यात्रा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुष्पवर्षा, स्वागत द्वार, छत्री एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी। कंगारू ग्रुप के चेयरमैन विश्वा जैन कंगारू ने कहा कि रथयात्रा केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे, सेवा और मानवता का संदेश देने वाला महोत्सव है। होटल महाराजा रिजेंसी के



सुखदर्शन जैन भोला ने कहा कि पिछले 29 वर्षों से यह यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जा रही है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मौके सतीश गुप्ता, अनिल सलूजा, राजिन्दर छाबड़ा ओटोया, कैलाश लड्डा, केवल बुद्धिराजा, संजय जैन बरनाला, अश्वनी जैन बरनाला, राजेश जैन बॉबी, विकास गोयल विककी, संजीव गुप्ता



स्टॉक एक्सचेंज, मुकेश घई, हरीश जैरथ बिट्टू, सुनील मेहरा, विवेक गुप्ता, मोहन लाल गुप्ता, अनिल राय, प्रजांत सलूजा, सतीश वर्मा रॉयल्टी ज्यूलर्स, कपिल गुप्ता किंगडम, लोकेश सूद, सुभाष डंग, बनवारी हरजाई, चंद्रसेन भोला, मिंटू कालिया, कुलदीप छाबड़ा मिंटू, राहुल अभी बंटी, मधुसूदन सूद, कनन लुथरा, संजीव पोपली, बांबी मल्होत्रा, अमित भगत मुन्ना आदि उपस्थित थे।

लोगों ने खुद बनाई सुरक्षा दीवार, कांग्रेस इंचार्ज बोले- चार साल में भी काम अधूरा



लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

वार्ड नंबर-81 के कांग्रेस इंचार्ज मंगा शर्मा ने सोमवार को क्षेत्रवासियों के सहयोग से नाले के किनारे गलियों के सामने पक्की दीवार बनवाई। उनका कहना है कि हर साल बरसात के दौरान नाले का गंदा पानी मोहल्ले में घुस जाता है, जिससे लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मंगा शर्मा

ने बताया कि रंजीत पार्क के साथ श्मशानघाट तक नाला ढकने की परियोजना कांग्रेस सरकार के समय मंजूर हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के चार साल बाद भी निगम इस काम को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की लापरवाही और धीमी कार्यप्रणाली के कारण क्षेत्र के लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वर्ष 2024 में मोहल्ला निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

प्रशासन का डंडा: दाना मंडी में रेत माफिया पर मार्केट कमेटी की कार्रवाई

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

सलेम टाबरी के अधीन आने वाली दाना मंडी में वर्षों से जमे रेत माफिया पर मंगलवार सुबह आखिरकार प्रशासन का डंडा चल ही गया। लंबे समय से नोटिसों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ मार्केट कमेटी ने पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुरजीत सिंह गिल के नेतृत्व में डीएमओ गुरमत्पाल सिंह, सचिव हरिंदर सिंह गिल, करीब 35 से 40 कर्मचारियों और भारी पुलिस बल ने मंडी में एक साथ दबिश दी। टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रखी गई रेत जब्त कर ली और



कब्जाधारियों को मौके पर ही सख्त चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करते हुए अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम पूरी कार्रवाई पर डटी रही और अभियान बिना रुके जारी रखा। कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों ने अपना सामान हटाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अधिकारियों ने इसे अंतिम मौका मानते हुए 24 घंटे की मोहलत तो दे दी, लेकिन साफ कर दिया कि इसके बाद किसी तरह की

और चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते आखिरकार सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
■ 2024 में भी दर्ज हुआ था मामला... अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024 में भी छह लोगों के खिलाफ अवैध कब्जे और नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुईं और सरकारी जमीन पर कब्जे लगातार बने रहे। बार-बार की चेतावनियों के बाद भी हालात नहीं सुधरे, जिसके चलते मंगलवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। मार्केट कमेटी के सचिव हरिंदर सिंह गिल ने कहा कि संबंधित लोगों को नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने हर बार नोटिसों को नजरअंदाज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की मोहलत अंतिम है। इसके बाद किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

स्नान यात्रा 108 प्रकार के सात्विक भोग अर्पित, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ स्नान यात्रा महोत्सव

हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से इस्कोन परिसर हुआ भक्तिमय

अर्शदीप भट्टी | लुधियाना
समर न्यूज़

इस्कोन मंदिर सिविल लाईंस, लुधियाना में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा महोत्सव अत्यंत भव्य एवं भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान के दिव्य अभिषेक, संकीर्तन एवं महाप्रसाद का लाभ प्राप्त किया। मंदिर अध्यक्ष नरोत्तमानंद दास ने अपने संबोधन में स्नान यात्रा महोत्सव के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जगन्नाथ स्नान यात्रा भगवान



की असीम कृपा का प्रतीक है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी का 108 पवित्र कलशों से दिव्य अभिषेक किया जाता है। इस महोत्सव के दर्शन एवं सेवा से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, शुद्ध भक्ति तथा भगवान

की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महोत्सव के दौरान मंदिर के यूथ फोरम के युवाओं द्वारा उत्साहपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का हरिनम संकीर्तन किया गया, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरस एवं आध्यात्मिक उत्सास से गूंज उठा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी



संकीर्तन में भाग लेकर भगवान के पावन नाम का कीर्तन किया। इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी का 108 पवित्र कलशों से दिव्य स्नान (महाअभिषेक) कराया गया। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा प्रेम एवं श्रद्धा से तैयार किए गए 108 प्रकार के

सात्विक भोग भगवान को अर्पित किए गए। आकर्षक पुष्प सज्जा, भजन-कीर्तन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए इस महोत्सव ने सभी भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारा एवं



महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्नान यात्रा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा का अनुपम संगम बनकर सभी भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहा।



नीलकमल मोनू | लुधियाना
समर न्यूज़

संपर्क किया और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर पार्षद निक्कू भारती ने विधायक पप्पी का स्वागत करते हुए कहा कि जनता की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है और क्षेत्र के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।